APPROPRIATION NO. (5) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : On behalf of Shri Pranab Mukherjee : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise Payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1983-84.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave by granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1983-84."

The Motion was adopted.

**SHRI PATTABHI RAMA RAO : I introduce the Bill.

**SHRI PATTABHI RAMA RAO : I beg to move :

"That the Bill to authorise Payment and appropriation of centain further sums from and out of the Consolidated Fund of india for the services of the financial year 1983-84, be taken into consideration."

MR. DEPUTY SPEAKER : *Motion moved* :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1983-84, be taken into consideration."

Mr. Paswan.

*Published in Gazette of India Extraordinary. Part II, Section 2 dated 9-12-1983.

**Introduced with the recommendation of the President.

**Moved with the recommendation of the President.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन विषयों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूँगा। मैं बतलाना चाहूंगा कि क्यों इसका विरोध कर रहा हूं। आज सबेरे इसी सदन में मैंने कोल इण्डिया के सम्बन्ध में मामला उठाया था। इन्होंने इसके लिए भी पैसा माँगा है। यदि आप कोल इण्डिया के फंक्शनींग को देखें तो पता चलेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। नेशनलाइजेशन से पहले वहाँ के लोगों को आश्वासन मिला था कि अधिक से अधिक राहत और रोजगार मिलेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार के लोगों का जो स्थान है वह एक मजदूर से ऊंचा नहीं उठ सका। उसका उद्देश्य था कि जो मीडियेटर्स हैं उनको खत्म करके सीधे लोगों तक राहत पहुँचाने का काम किया जायेगा। लेकिन वहाँ ठेकेदारों की फौज खड़ी हो रही है। मशीनीकरण का मामला यह है कि जो लोडिंग पाइन्ट्स हैं, वहाँ भी मशीनों का अनुपयोग हो रहा है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कोल इण्डिया के चेयरमैन श्री गुजराल साहब ने बहुत कोशिश की कि कुछ काम किया जाए। लेकिन 80 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिला। यह सारा रुपया राइट-आफ कर दिया गया। वहाँ के 55 एम्पलाइज़ को 50 करोड़ का फायदा होने वाला था। मैनेजमेंट और चेयरमैन का काम यह रहा है कि किस तरह 75 करोड़ के लाभ के बजाय सरकार को 70 करोड़ का मुनाफा करके दिया जाए। ऐसी चाल वहाँ चली गई है।

मेरे पास डायरेक्टर पर्सनल श्री वी० मनोहर के नाम से 9-11-83 का सिक्रेट डाक्यूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्सन्स आफ दी चेयरमैन सी० आई० एल० जो 6 नवम्बर

[श्री राम विलास पासवान]

1983 को कोयला नगर गैस्ट हाऊस से दी गई। इसके छठे पाइन्ट को देखें।

The sixth instruction read like this :

> If strength of 2000 miners/loaders is to be knocked off on account of over-stay/abandonment of employment, disciplinary action, the Company can recruit 1000 young miners/loaders out of tribals within November 1983 to augment the strength of miners/loaders (underground).

सीक्रेट मीटिंग में यह तय किया जाता है कि एम्पलाईज को किस तरह रिट्रेंच या ससपेंड किया जाए और तृतीय पे कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने से सरकार का जो 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा, उस घाटे की पूर्ति इस तरह की जाए, जिसे 70 करोड़ रुपए की बचत होगी, बल्कि सरकार के पास 20 करोड़ रुपया बच जाएगा। यह एक मजदूर-विरोधी कदम है। अभी तक एक हजार लोगों को डिसचार्ज किया जा चुका है, दो हजार एम्पलाईज को ससपेंड किया जा चुका है और तीन हजार एम्पलाईज को नोटिस दिया जा चुका है। इस स्थिति में वहां अशांति नहीं होगी, तो क्या होगा ? जिस मजदूर को रिट्रेंच या ससपेंड किया गया है, या किया जाएगा, उसके आश्रितों में से किसी को कमपेशनेट ग्राउंड्ज पर नौकरी भी नहीं दी जाएगी।

कोल इंडिया में व्यापक भ्रष्टाचार है। उसका हैडआफिस बिहार से बाहर है। बिहार के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं होता और बिहार सरकार को रेवेन्यु प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोल इंडिया को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। जब तक वहाँ पर वर्तमान चेयरमैन हैं, जो भ्रष्टाचार पैदा करता है, तब तक कोल इंडिया को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए।

जब से बिहार के वर्तमान मुख्य मंत्री आए हैं, तब से वहाँ पर कई स्थानों पर गोली चली है। 12-8-83 को इसकी घोषणा हुई और 12-8-83 को भवनाथपुर में गोली चली, 18-8-83 को घरहारा और बालापुर सौदा में गोली चली, 25-8-83 को रक्सौल, पूर्वी चम्पारन में गोली चली··· (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही (वेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन श्री चन्द्रशेखर सिंह मुख्य मंत्री बने, उसी दिन गोली चली। माननीय सदस्य गलतबयानी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य मंत्री का शपथ-ग्रहण 14 तारीख को हुआ था, जबकि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 12 तारीख को गोली चली।

(व्यवधान)

SHRI HARISH RAWAT (Almora): He is discussing the law and order situation in the State. How far is it relevant to these Budget Demands ?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : He wanted to alert all the other Members.

श्री हरीश रावत : जनता-लोकदल काम्बीनेशन के लोग गोली चला रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ पर लेंड रिफार्म्ज करना चाहती है। उसको रोकने के लिए वे लोग गोली चला रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : श्रीमती कृष्णा साही ने कहा है कि मुख्य मंत्री ने 14 तारीख को ओथ ली। मैंने कहा है कि 12

तारीख को उनके नाम की घोषणा हुई और उसी दिन गोली चली। 14 जगहों पर गोली चली है और माननीय सदस्या को यह मालूम है।

श्रीमती कृष्णा साही : आपके इन्स्टीगेशन से ऐसी घटनाएं हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको प्रोसीडिंग्ज से निकाल दीजिए। जब वह गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो उसे प्रोसीडिंग्ज में नहीं रहना चाहिए।

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : How far it is relevant, I do not know.

SHRI RAM VILAS PASWAN : If I have made a wrong statement; I will resign, and if the Member is wrong she has to resign.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What you say, and what she has said, have gone on record. You say that it is a wrong statement. She says that it is not a wrong statement. It has all come on record.

श्री राम विलास पासवान : मैं माननीय सदस्या की भावना का आदर करते हुए ला एंड आर्डर सिचुएन में नहीं जाऊंगा।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय सदस्य का कहना है कि यह बात सत्य तो है, लेकिन वह नहीं चाहतीं कि वह रिकार्ड पर रहे।

श्री राम विलास पासवान : देश की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना हम सब का कर्तव्य है। सप्लीमेंटरी डिमांड्ज में आई० एम० एफ० से पैसा लेने की बात कही गई है। दो दिन पहले मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे देश पर विदेशी कर्जा 23,000 करोड़ रुपए का हो गया है। सरकार देश के अन्दर फिनांशल इस्टीट्यूशन्ज से जो कर्जा ले रही है, वह 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इकानोमिक सरवे के मुताबिक 1950-51 में विदेशी कर्जा 32, 33 करोड़ रुपए था, जबकि आज वह 23,000 करोड़ रुपए हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक आत्म-निर्भर हों और विदेशी पैसे पर कम से कम निर्भर रहें।

इन मांगों में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात कही गई है। सरकार ने एन० आई० पी० की योजना बनाई है। उसकी तरफ़ से 20-सूत्री कार्यक्रम का बहुत हवाला दिया जाता है। लेकिन बावजूद वह अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस चीज के लिए पैसा ले रहे हैं? इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप जिस मद में पैसा दे रहे हैं, उसका सदुपयोग हो, वह उसी मद में खर्च किया जाय और वे ठीक से काम करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, **मांग संख्या 43 और 51—वित्त एवं गृह मंत्रालय** : कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए स्वतन्त्रता सेनानियों को मिल रही पेंशन की राशि को तीन सौ रुपये से बढ़ा कर पांच सौ रुपये माहवार करना आवश्यक है। गत बजट सत्र में विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर हुई बहस के क्रम में 18-3-1983 को मेरे द्वारा उठाये गये इसी प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार पेंशन वृद्धि पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा था—

"As the Hon. Members are aware of it, this question was raised on the floor of the House on earlier

[श्री रामावतार शास्त्री]

> occasions also and my colleague, the Home Minister has informed me just now that the Government are looking into the various aspects of it and shortly it will be possible to take a decision on it."

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है—सरकार वित्त मंत्री के इस आश्वासन को आश्वासन नहीं मानती है।

प्रधान मंत्री ने लोक सभा के इसी सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि स्वतन्त्रता सेनानियों को भारत-भ्रमण के लिये एक बार रेलवे पास दिया जायगा तथा गोवा मुक्ति संघर्ष में भाग लेने वाले सभी सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन दिया जायगा। इनके बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

हजारों नकली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की राशि मिल रही है और हजारों नकली व्यक्ति फरारी का सहारा लेकर पेंशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के स्वतन्त्रता सेनानी निदेशालय के कार्यालय में भ्रष्टाचार एवं कदाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। अन्य स्थानों की भी शिकायतें हैं। सरकार ने इन्हें रोकने के लिये कौन सी कार्यवाही की है ?

जीवन यापन के व्यय में वृद्धि को देखते हुए भूतपूर्व संसदों को मिल रही पेंशन की राशि को बढ़ा कर तीन सौ से 500 रुपये और 500 से बढ़ा कर 700 रुपये करना अत्यावश्यक हो गया है। उन्हें, रेलवे पास तथा कुछ अन्य सुविधायें देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। इनके विषय में उनके संगठन की ओर से प्रधान मंत्री को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की तीन किश्त बकाया पड़ गई हैं। सरकार के बार-बार आश्वासनों के बावजूद बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। केवल आश्वासनों से तो उनका पेट भरने वाला नहीं है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन्हें बकाया राशि कब तक चुका देने का विचार रखती है ?

मांग संख्या 12 : पटना के निकट फुलवारी शरीफ में बिहार शरीफ में बिहार पटसन मिल्स है। वहां करीब एक हजार मजदूर काम करते हैं। मालिकों ने उसे दो-तीन वर्षों से अकारण बंद कर रखा है। दो माह के वेतन, बोनस, आदि, भी बकाया पड़ा हुआ है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह हजारों लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये मालिकों पर दबाव डालकर कारखाने को खुलवाने की व्यवस्था करे अन्यथा उसे अपने हाथ में लेकर चालू करे और मजदूरों के बकायों का भुगतान करवा दे।

मांग संख्या 25—शिक्षा : इंडियन स्कूल आफ़ माइन्ज़, धनबाद, में भ्रष्टाचार एवं कदाचार का राज्य है। वहां डायरेक्टर की तानाशाही चलती है। वह जो चाहते हैं कर गुजरते हैं। एक समय का ऐतिहासिक एवं मशहूर संस्थान बर्बाद हो रहा है। वहाँ की व्यवस्था से न अध्यापक खुश हैं और न कर्मचारी। चार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, चार अन्य मुअत्तल हैं तथा औरों को तरह-तरह से तंग किया जा रहा है। संस्थान में घोर अशान्ति है जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ना स्वाभाविक

है। अत: वहाँ के डायरेक्टर का जमींदारी को समाप्त करने के लिये वर्तमान प्रबंध में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है अन्यथा स्थिति बिगड़ती जायगी। शिक्षा मंत्री को स्वयं इधर ध्यान देना चाहिये।

रांची स्थिति मेसरा में बिड़ला इंस्टीचूट आफ टेकनालाजी है। उसके असल मालिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं न्यायालयों के फैसलों के बावजूद वह रांची विश्वविद्यालय का कांस्टीचूएन्ट कालिज नहीं है। फिर भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसे आर्थिक सहायता किस आधार पर देता है ? उसे रांची विश्वविद्यालय कांस्टीचूएन्ट कालेज करना चाहिये और वहां के सभी नियम कानून उसके अध्यापकों-कर्मचारियों पर लागू होना चाहिये।

मांग संख्या 48—चिकित्सा : पटना में इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान नामक एक बड़ा ही उपयोगी अस्पताल है जिससे हृदय रोगियों की बड़ी सेवा हो रही है। वहाँ डाक्टरों-नर्सों आदि की अच्छी टोली भी है। परन्तु उसे और उपयोगी बनाने के लिये पहली किश्त में 12 लाख और दूसरी किश्त में 50 लाख रुपये की आवश्यकता है ताकि उसका बिस्तार ठीक से हो सके। ऐसा हो जाने से बिहार एवं अन्य राज्यों की बड़ी सेवा होगी। अत: सरकार को अविलम्ब उक्त संस्थान को एक भारी राशि अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मांग सं० 9—रसायन : बिहार के मुजफ्फरपुर में आई० डी० पी० एल० का कारखाना है। वहां हजारों मजदूर काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दो बार भारी विस्फोट हुआ था जिसमें दर्जनों मजदूर घायल हुए थे और कुछ की हालत चिन्ताजनक थी। करोड़ों रुपयों की भारी क्षति हुई थी इसकी उच्चस्तरीय जाँच की जानी चाहिये, घायल मजदूरों को उचित मुआवजा मिलना चाहिये, प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए, उसकी नई व्यवस्था अच्छे लोगों को लेकर की जाय ताकि कारखाना लाभ में चल सके और बिहार की जनता को लाभ हो।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबिल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त सरकार से जो तबक्कुआत हैं उनके मुताबिक मुल्क में ओरिएन्टल एजूकेशन हो। इस वक्त मुल्क की यह हालत है कि हमारा जो प्लानिंग है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलनी चाहिये थी ताकि जो इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद एजूकेशन हासिल करते हैं, उनको जोब्स मिलते लेकिन हमारी जो योजनाएं बन रही हैं, उनके अनुसार हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जह नहीं दी है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अन्दर और सारी स्टेट्स में लाखों नौजवान ग्रेजुएट्स और लाखों जवान प्रोफिशियेन्सी हासिल करने के बाद चार-चार, छः छः और दस-दस साल तक बेकार पड़े रहते हैं और हमारा जो इंटेलीजेंसिया है, जो पढ़ा-लिखा तबका है, जो इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही कीमती साबित हो सकता था, वह हजारों की तादाद में मुल्क छोड़ने पर मजबूर है और इस मुल्क को छोड़ कर वह नौजवान तबका अमेरीका और योरुप जा रहा है। इसके अलावा जो स्किल्ड तबका है, वह भी बाहर जा रहा है। इस तरह से मुल्क की एक बहुत बड़ी पूंजी हमारे हाथों से जा रही है। इस तरफ योजनाओं में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

(श्री अब्दुल रशीद काबुली)

इस मुल्क में जहां हजारों नौजवान बेकार हैं, वहां अस्पतालों में अगर कोई आदमी बीमारी का इलाज कराने जाता है, तो वहां पर दवाइयां बाहर से उसे खरीदनी पड़ेंगी और उसका इलाज उसके पैसे से ही होगा और मामूली से मामूली दवा के लिए भी उसे मार्केट जाना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन और मेम्बर आफ पार्लियामेंट के लिए कुछ रियायत है लेकिन जो मुल्क के करोड़ों लोग हैं, उनके लिए कोई कन्सेशन नहीं है। वे खर्च किया हुआ पैसा वापस नहीं ले सकते। हमारी सरकार कहती है कि हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अमल की कसौटी पर देखा जाए, तो आप देखेंगे कि ये इसमें कितने कामयाब हुए हैं और कितना लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आज इस देश में हो क्या रहा है। महात्मा गांधी के इस देश में आज करोड़ों रुपया एशियाड पर खर्च हो रहा है और दूसरी अनप्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्च हो रहा है लेकिन गरीबों के लिए क्या हो रहा है। बहुत सारा रुपया चोग्म पर और दूसरी चीजों पर खर्च हो रहा है और आज भी इस मुल्क में गवर्नर एक बादशाह से कम नहीं है। लाखों रुपया आज उस पर खर्च हो रहा है और प्रेसीडेंट आफ़ इन्डिया की बात ही दूसरी है। मेरे मन में उनके प्रति आदर है क्योंकि कांस्टीट्यूशन ने उनको एक इज्जत, सम्मान दिया है लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज भी इस मुल्क में यह काम एक जागीरदार के तौर पर चल रहा है। ब्रिटिश टाइम्स में जो उस जमाने में इनका एक इक्तदार था, गैर-मुल्की हुकूमत के जमाने में सफेद चमड़ी वालों की जो पोजीशन थी, वही ढांचा आज भी इस मुल्क में चला आ रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। आज मुल्क में गवर्नर बना दिये हैं और जो बड़-बड़ी जगहों पर, ऊंची जगहों पर लोगों को बैठा दिया है, वे उन महलों में रहते हैं, जिनमें ब्रिटिश टाइम्स में बड़े-बड़े लार्ड्स रहते थे। वे बड़े लार्ड्स के रहने की जगहें हैं और वे महलात हैं जोकि नवाबों और राजाओं के महलात थे। इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि इस गरीब मुल्क में हालत यह है कि आज मुखमरी से हजारों लोग मर रहे हैं और जहां पर ड्राऊट्स पड़ा है, वहां पर लाखों लोग, मजदूर और किसान तबाह हुए हैं। उन लोगों का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आज इस मुल्क में लाखों ऐसे बोंडेड लेबर हैं, जिनकी दरयाफ्त कभी हरियाणा में होती है और कभी राजस्थान में होती है और उन गरीब लोगों को आज भी खरीदा जाता है और उनसे जबरन मजदूरी ली जा रही है। आज उनमें पहले के गुलामों में कोई अन्तर नहीं रह गया है और उनसे वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है जैसा कि अफ्रीका में और दूसरी जगहों में गुलामों के साथ किया जाता था। आज हमारे माडर्न इन्डिया की यह बात है, जिसको मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

अब मैं अपनी स्टेट की तरफ आना चाहता हूं। हमारे यहां धान पैदा करने के लिए बड़ी जमीन है। खुदा के फजल से हिन्दुस्तान की जमीन ऐसी है जो सोना ही सोना उगलती है लेकिन शर्त इस बात की है कि हम इसका फायदा उठाएं। मैं आपकी इजाजत से गवर्नमेंट को यह बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी का क्राइसिस है। हमारे यहां बिजली बहुत कम पैदा होती है लेकिन सरकार ने इस बारे में कभी परवाह नहीं की और हमारी बद-किस्मती यह है कि वह इसी में फंसी रहती

है कि किस सूबे में कौन सी पार्टी राज्य करती है। इसी चक्कर में फंसे होने के कारण इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और इस वजह से मुल्क का बहुत नुक्सान हुआ है। हमारे जम्मू व काश्मीर में हजारों नदी-नाले हैं और हमारे यहां नदी-नालों का इतना पोटेंशियल है कि आपके लिए वहां पर 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं और पूरे नदर्न इन्डिया को, पूरे नदर्न ग्रिड को बिजली हम दे सकते हैं। उड़ी का प्रोजेक्ट जो बना वह कागजों पर ही बना। उड़ी प्रोजेक्ट से न केवल उस स्टेट को बल्कि पूरी नदर्न टेट्स को बिजली सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसमों में दी जा सकती है। इसी तरह से दूलहस्ती का प्रोजेक्ट है, जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। इसलिए नहीं हुआ कि स्टेट और सेन्टर के रिलेशंस ठीक नहीं थे। इसी वजह से वह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो सका है। आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे मुल्क का कितना बड़ा नुक्सान हो रहा है।

मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर या किसी और जगह पर खुद यह कहा था कि पब्लिक सेक्टर के बारे में प्रोग्रेस के जो अफसाने बताये जा रहे हैं, असल में जाहिर यह होता है कि पब्लिक सेक्टर तबाही की तरफ जा रहा है। पब्लिक सेक्टर की बिलों पर आज प्राइवेट सेक्टर फायदा उठा रहा है और प्राइवेट सेक्टर का डवलपमेंट हो रहा है। जब हमारे यहां सोशलिज्म है तो हमें पब्लिक सेक्टर को ही अपने यहां रखना चाहिए लेकिन हम दोनों को चला रहे हैं। पब्लिक सेक्टर तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि प्राइवेट सेक्टर को बीच में से न हटाया जाए। प्राइवेट सेक्टर की मुल्क में इस वजह से तरक्की हो रही है क्योंकि उससे सारी पोलिटिकल पार्टीज को, मैं किसी एक पोलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, इमदाद हासिल होती है और उस इमदाद से हम इलेक्शन लड़ते हैं।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से करोड़ों रुपये का कालीन और एम्ब्रायडरी बाहर जाता है। खुदा के वास्ते उस पर से आप एक्साइज ड्यूटी हटाइये। हमारे यहां जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें पेकिंग के लिए दो करोड़ क्यूबिक फीट लकड़ी का इस्तेमाल होता है क्योंकि फ्रूट लकड़ी के बक्सों में पैक किया जाता है। अगर हमें फ्रूट्स के लिए फॉरन पैकिंग पेपर मंगाने की इजाजत दे दी जाए और उस पर एक्साइज ड्यूटी न लगे तो हमारे मुल्क में इतनी लकड़ी बच सकती है।

ये सारी बातें हैं जिन पर कि हमें तवोज्जह देनी चाहिए।

شری عبدالرشید کابلی (شری نگر):

آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب! میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سرکار سے جو توقعات ہیں ان کے مطابق ملک میں آرنیٹل ایجوکیشن ہو۔ اس وقت ملک کی یہ حالت ہے کہ ہمارا جو پلاننگ ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکری ملنی چاہیئے تھی۔ تاکہ جو اتنی محنت اور مشقت کے بعد ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان کو جو ملتے لیکن ہماری جو یونیورسٹیز بن رہی ہیں اُن کے انوسار ہمیں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر اور ساری اسٹیٹس میں لاکھوں نوجوان گریجویٹس اور لاکھوں جوان پرافیشینسی حاصل کرنے کے بعد چار چار، چھ چھ اور دس دس سال تک بیکار پڑے رہتے ہیں اور ہمارا جو انٹیلیجینسیا ہے

میں سفید چمڑی والوں کی جو پوزیشن تھی وہی ڈھانچا آج بھی اس ملک میں چلا آرہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ آج ملک میں گورنر بنا دئے ہیں اور جو کہ بڑی بڑی جگہوں پر اونچی جگہوں پر لوگوں کو بٹھا دیا ہے۔ وہ ان محلوں میں رہتے ہیں جن میں برٹش ٹائمس میں بڑے بڑے لارڈس رہتے تھے۔ وہ بڑے لارڈس کے رہنے کی جگہیں ہیں اور وہ محلات ہیں جو کہ نوابوں اور راجاؤں کے محلات تھے۔ اس بنا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اس بات کو دھیان میں رکھے کہ اس غریب ملک میں حالت یہ ہے کہ آج بھکمری سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور جہاں پر سُراؤنٹس پڑا ہے وہاں پر لاکھوں لوگ مزدور اور کسان تباہ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی سرکار کو دھیان رکھنا چاہیئے۔

آج اس ملک میں لاکھوں ایسے بونڈیڈ لیبر ہیں جن کی دریافت کبھی ہریانہ میں ہوتی ہے اور کبھی راجستھان میں ہوتی ہے اور ان غریب لوگوں کو آج بھی خریدا جاتا ہے اور اُن سے جبرن مزدوری لی جارہی ہے۔ آج ان میں اور پہلے کے غلاموں میں کوئی انتر نہیں رہ گیا ہے۔ اور ان سے ویسا ہی برتاؤ کیا جارہا ہے جیسا کہ افریقہ میں اور دوسری جگہوں میں غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے ماڈرن انڈیا کی یہ بات ہے جس کو میں سرکار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔

اب میں اپنی اسٹیٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں دھان پیدا کرنے کے لئے بڑی زمین ہے۔ خدا کے فضل سے ہندوستان کی زمین ایسی ہے جو سونا ہی اُگلتی ہے۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس کا فائدہ اُٹھائیں۔ میں آپ کی اجازت سے گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اس ملک کی ترقی کے لئے بہت ہی قیمتی ثابت ہوسکتا تھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہے اور اس ملک کو چھوڑ کر وہ نوجوان طبقہ امریکہ اور یورپ جارہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسکلڈ طبقہ ہے وہ بھی باہر جارہا ہے۔ اِس طرح ملک کی ایک بہت بڑی پونجی ہمارے ہاتھوں سے جارہی ہے۔ اس طرف یوجناؤں میں کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے۔

اس ملک میں جہاں ہزاروں نوجوان بیکار ہیں وہاں ہسپتالوں میں اگر کوئی آدمی بیماری کا علاج کرانے جاتا ہے تو وہاں پر دوائیاں اُسے باہر سے خریدنا پڑیں گی اور اس کا علاج اس کے پیسے سے ہی ہوگا اور معمولی سے معمولی دوا کے لئے بھی اسے مارکٹ جانا پڑے گا۔ سرکاری ملازمین اور ممبر آف پارلیمنٹ کے لئے کچھ رعایت ہے لیکن جو ملک کے کروڑوں لوگ ہیں ان کے لئے کوئی کنسیشن نہیں ہے۔ وہ خرچ کیا ہوا روپیہ واپس نہیں لے سکتے۔ ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے سواستھ کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن عمل کی کسوٹی پر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ روپیہ آج اس پر خرچ ہو رہا ہے اور پریسیڈینٹ آف انڈیا کی بات ہی دوسری ہے۔ میرے من میں اُن کے پرتی آدر ہے کیونکہ کانسٹی ٹیوشن نے ان کو ایک عزت، سمان دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج بھی اس ملک میں یہ کام ایک جاگیردار کے طور پر چل رہا ہے۔ برٹش ٹائمس میں جو اس زمانے میں ان کا ایک اقتدار تھا۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے

ہم دونوں کو چلا رہے ہیں۔ پبلک سیکٹر جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں سے نہ ہٹایا جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی ملک میں اس وجہ سے ترقی ہو رہی ہے کیونکہ اس سے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا امداد حاصل ہوتی ہے اور اس امداد سے ہم الیکشن لڑتے ہیں۔

میں یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر سے کروڑوں روپے کے قالین اور امبرائڈری باہر جاتا ہے۔ خدا کے واسطے اس پر سے آپ ایکسائز ڈیوٹی ہٹائیے۔ ہمارے یہاں جو فروٹ انڈسٹری ہے اس میں پیکنگ کے لئے دو کروڑ کیوبک فٹ لکڑی کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ فروٹ لکڑی کے بکسوں میں پیک کیا جاتا ہے اگر ہمیں فروٹس کیلئے فوراً پیکنگ پیپر منگانے کی اجازت دیدی جائے اور اس پر ایکسائز ڈیوٹی نہ لگے تو ہمارے ملک میں اتنی لکڑی بچ سکتی ہے۔

یہ ساری باتیں ہیں جن پر کہ ہمیں توجہ دینا چاہیئے۔

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों पर बोलते हुए आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में एक आर० पी० एच० एम० जूट मिल, कटिहार है। उसका प्रबंध ग्रहण 30 अप्रैल, 1978 को हुआ था और उसका राष्ट्रीकरण 11 दिसम्बर, 1980 को हुआ था। इसके सम्बन्ध में मैंने कट मोशन भी दिया है। इस मिल को नवीकरण के लिए एन० जे० एम० सी० को सौंपा गया था। उसके प्रबंधन में ही यह मिल है। लेकिन उसके प्रबंध में इसकी हालत नहीं सुधरी है।

एन० जे० एम० सी० ने इसके नवीकरण के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसको कि प्लानिंग कमीशन ने स्वीकृत नहीं

سب سے بڑا کرائسس انرجی کا کرائسس ہے۔ ہمارے یہاں بجلی بہت کم پیدا ہوتی ہے لیکن سرکار نے اس بارے میں کبھی پرواہ نہیں کی۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اسی میں پھنسی رہتی ہے کہ کس صوبہ میں کونسی پارٹی راجیہ کرتی ہے۔ اسی چکر میں پھنسے رہنے کے کارن اس طرف دھیان نہیں دیا گیا ہے۔ اور اس وجہ سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے۔

ہمارے جموں و کشمیر میں ہزاروں ندی نالے ہیں اور ہمارے یہاں ندی نالوں کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کے لئے وہاں پر دس ہزار میگاواٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور پورے ناردرن انڈیا کو پورے ناردرن گرڈ کو بجلی ہم دے سکتے ہیں۔ اڑی کا پروجیکٹ جب بنا وہ کاغذوں پر ہی بنا۔ اڑی پروجیکٹ سے نہ کیوں اس اسٹیٹ کی بلکہ پوری ناردرن اسٹیٹ کی بجلی سردی اور گرمی دونوں ہی موسموں میں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دلہستی کا پروجیکٹ ہے۔ اس کی طرف میں سرکار کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں۔ اس لئے نہیں ہوا کہ اسٹیٹ اور سینٹر کے ریلیشنس ٹھیک نہیں تھے اسی وجہ سے وہ پروجیکٹ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔

میں پبلک سیکٹر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہاں پر یا کسی اور جگہ پر خود یہ کہا تھا کہ پبلک سیکٹر کے بارے میں پروگرس کے جو افسانے بنائے جا رہے ہیں اصل میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پبلک سیکٹر کی بنا پر آج پرائیویٹ سیکٹر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب ہمارے یہاں سوشلزم ہے تو ہمیں پبلک سیکٹر کو ہی اپنے یہاں رکھنا چاہیئے۔ لیکن

(प्रो० अजीत कुमार मेहता)

किया। मैं यहां यह आरोप लगाना चाहता हूं कि चूंकि एन० जे० एम० सी० का दफ्तर वेस्ट बंगाल में है इसलिए वे यह नहीं चाहते कि बिहार में कोई जूट मिल उन्नति कर सके। उन्होंने अपनी स्कीम सबमिट करने के बाद मेमोरेण्डम में यह कहा कि नवीकरण के बाद भी यह मिल घाटे में चलेगा। लेकिन मेरा यह दावा है कि नवीकरण के बाद निश्चित रूप से यह मिल लाभ में चलेगा।

एन० जे० एम० सी० की जो यूनिट्स वेस्ट बंगाल में हैं, उनमें रिवाइज्ड वेज पालिसी के अनुसार वेतन वृद्धि हुई है लेकिन इस मिल में जो कि बिहार में है वेतन वृद्धि लागू नहीं की गई है। इसके सम्बन्ध में मजदूर यूनियनों और आर० पी० एम० एम० जूट मिल के बीच में वाणिज्य मंत्री के सामने फैसला हुआ था।

वेतनवृद्धि और पुराने वेतन के बीच का जो अंतर हो गया है उसका आधा उनको तत्काल मिलने लगेगा और आधे के लिए कहा गया कि इस मिल को 50 लाख रुपया बिना सूद के कर्ज के रूप में दिया गया है, उसके आधार पर मिल का नवीनीकरण कर लिया जाए और लाभ होने के बाद मजदूरों को वेतन वृद्धि का शेष आधा भाग दे दिया जाय। 50 लाख रुपया उनको मिल भी गया। लेकिन मेरा आरोप है कि मिल प्रबंधकों ने उस रुपए का दुरुपयोग किया। हाल में दूसरे सदन के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र मोहन और लोकसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री युवराज ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि मिल के प्रबंधकों ने 50 लाख रुपए का दुरुपयोग किया है। (व्यवधान)

इन लोगों के अभ्यावेदन पर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरे सदन में एक प्रश्न के उत्तर में जो सूचना मिली है उसके अनुसार कहा गया है कि 50 लाख पूरा तो नहीं, 20 लाख खर्च किया गया है। लेकिन मेरा कहना है कि 20 लाख भी उचित खर्च नहीं किया गया है। सारे पैसे का दुरुपयोग किया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों ने हाउस रेंट आलाउंस की मांग रखी है। एन० जे० एम० सी० के दूसरे यूनिट में यह मिल रहा है। पर उनको यह कहा जा रहा है कि पहले बिहार सरकार से लेजसलेशन पास कराइए तब आपको मिलेगा। तुर्रा यह है कि वहां के अधिकारियों को तो मिल रहा है लेकिन मजदूरों को नहीं मिल रहा। तो मेरी मांग है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER : You must know the time limit. This is an Appropriation Bill. We want to give chance to all the Members. You must adjust.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : At least allow me to complete my points. I shall finish in one or two minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : We should have taken Private Members Business at 15.00 hrs. Sometimes you have to adjust.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : You have allowed others to speak for fifteen minntes.

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani) : This Bill may be taken up on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Government wants it to be passed to-day.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Government has to spend money.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : Please allow me to complete my points.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : MR. Deputy Speaker, at this rate you would not be able to close to-day.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I have taken only two minutes.

SHRI PATTABHI RAMA RAO : He has taken ten minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Your Party has already taken time. All right, how much time do you want ?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : I want five minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Let me see that you finish it in five minutes.

प्रो० अजित कुमार मेहता : कटिहार जूट मिल 5 जुलाई, 1982 से बंद है जिसकी वजह से मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। बारह मजदूर अब तक मर चुके हैं। किसी भी प्रकार से मिल को खुलवाने का प्रबन्ध करें। एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एडमिशन पालिसी चेंज कर दी गई है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जो सुविधा मिलती थी, वह बंद हो गई है। जवाहलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना के जो मुख्य उद्देश्य थे, उनका हनन हो रहा है। इसकी नीति इलाइट लोगों के पक्ष में tilt (झुक) रही है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी एडमिशन पालिसी पर पुनर्विचार करके पूर्ववत कर दें।

मेरा आखिरी मुद्दा कोयलकारो हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में है। इस प्रकार की परियोजना लागू होने पर आदिवासियों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। वे अपने घर से भी उखड़ जाते हैं। आदिवासी इतने पिछड़े हुए हैं कि एक दफा उखड़ने के बाद उनको भीख मांगनी पड़ती है अतः उनका प्रतिरोध है। मेरा सुझाव है कि आप उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध करें। उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दें कि वे अपनी जीविका चला सकें। आपको तभी सफलता मिलेगी। इसके साथ-साथ मेरा एक सुझाव और है। दक्षिण बिहार कोयला बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तरीकरणपुरा कोयला क्षेत्र में जहां पानी और कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है, वहां आप सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्यों नहीं स्थापित करते हैं ? इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Prof. N.G. Ranga.

PROF. N.G. RANGA : Sir, let the Minister reply.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Ram Lal Rahi.

PROF. N.G. RANGA : Sir, I do not understand any relevance at all. I gave up my right to speak because you were in hurry. I thought the Minister would speak immediately.

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : माननीय मंत्री जी ने जो मांगें पेश की हैं, उसमें केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। सदन का समय जाया नहीं करूंगा और न मंत्री जी मेरी बात से उबेंगे। पहली बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन की बढ़ोत्तरी का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इस देश के अन्दर अब बहुत थोड़े से लोग बचे हैं। मेरा ख्याल है सौ, दो सौ या तीन सौ ही होंगे। इसलिए, कम-से-कम पाँच सौ रुपए महीना पेंशन इन लोगों को दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाढ़ से हर साल न मालूम कितना नुक्सान है। खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं और करोड़ों टन

(श्री राम लाल राही)

गल्ला जो किसान उत्पादित करता है, सब बेकार हो जाता है।

इसका परिणाम यह होता है कि भारत द्वारा गल्ले के मामले में दूसरे देशों के सामने हाथ पसारने की स्थिति पैदा होती है। मंत्री महोदय को चाहिए था कि वह अनुपूरक मांगों में बाढ़ को रोकने के बारे में कोई व्यवस्था करने का प्रावधान करते, इस दिशा में कुछ शुरुआत करते, कोई उपाय सोचते। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जवाब देते समय बताएं कि वह बाढ़ों को स्थायी रूप से रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। क्या सरकार के सामने केवल यही चारा रह गया है कि जहां बाढ़ आए, वहां लोगों में एक-दो किलो आटा, मिट्टी का तेल और दीयासलाई वगैरह बांट दें ? सरकार पिछले तीस-पैंतीस साल से निरन्तर यही करती रही है। वह कब तक यह करती जाएगी ? करोड़ों रुपए इस तरह बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने में असफल रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार बाढ़ को रोकने के बारे में कोई ठोस कदम उठाए, ताकि लोगों को राहत मिले।

मैंने जो कटौती-प्रस्ताव दिए हैं, उनके द्वारा मैंने चार आइटम्ज पर बल दिया है। उनमें पहला आइटम है सूखा और बाढ़ और दूसरा है उर्वरक। जनता शासन के जमाने में ही पहला अवसर आया था, जब श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने, जब वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय सम्भाले हुए थे, खाद के दामों में कमी की थी, जिससे किसानों को राहत मिली थी। लेकिन यह सरकार तो निरन्तर दाम बढ़ाती चली जा रही है और किसान पर बोझ लादती चली जा रही है। सरकार खाद के नये कारखाने लगा रही है, खाद का उत्पादन बढ़ रहा है और बाहर से भी खाद आयात किया जा रहा है। फिर किसान पर बोझ क्यों लादा जा रहा है ?

जब पेट्रोल 30 परसेंट पैदा होता था, तब उसके दाम इतने नहीं बढ़ते थे। लेकिन जब 60 परसेंट पेट्रोल यहां पर पैदा हो रहा है, तब हर तीसरे महीने दाम बढ़ने लगे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है ? मंत्री महोदय कह सकते हैं कि हम अधिक उत्पादन में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए ज्यादा पैसा ले रहे हैं। जब वह ज्यादा उत्पादन के लिए पैसा लगा रहे हैं, तब वह लोगों को भी तो कुछ राहत दें—अगर वह दस पैसे में से छः पैसे उत्पादन में लगा रहे हैं, तो वह चार पैसे किसान और जनता को राहत दें। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, तो जन-असंतोष बढ़ेगा।

प्रौढ़ शिक्षा हमारे देश में एक अजीब तरीके का रोग बन गया है। चाहे महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा हो या पुरुषों की, उसके नाम पर देश का करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। किसी भी गांव में, किसी ब्लाक में, किसी क्षेत्र में कोई क्लासिज़ नहीं चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस योजना को बन्द किया जाए। अगर इसको चलाना ही है, तो सरकारी स्कूलों के मास्टरों को इसमें लगाया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और वे हफ्ते में एक-दो घंटे की एक क्लास लें। हफ्ते में एक घंटा पढ़ाने से ही काम चल सकता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो मैं यह मान कर चलता हूं कि अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्तारूढ़ दल अपने आदमियों को सहायता देने के उद्देश्य से इस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है।

SHRI PATTABHI RAMA RAO : Mr. Deputy Speaker, Sir, starting from

Shri Ram Vilas Paswan to Shri Ram Lal Rahi, five Hon. Members have spoken on the Bill. (*Interruptions*) I am very grateful to all of them. I have noted the points made by them and all that is possible would be done.

MR. DEPUTY SPEAKER : I shall now put the motion for consideration to the vote of the House.

The question is :

"That the Bill to acthorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1983-84, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we will take up the Clauses.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 *and* 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:

"That Clause 1, the Enacting formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI PATTABHI RAMA RAO : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.46 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Sixty-Sixth Report

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I beg to move :

"That this House do agree with the Sixty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 7th December, 1983."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Sixty-Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 7th December, 1983."

The motion was adopted.